



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]

नई दिल्ली, बुध्मतिवार, नवम्बर 14, 1996/कार्तिक 23, 1918

No. 382]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 1996/KARTIKA 23, 1918

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1996

सा.का.नि. 523(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में जहाँ-तहाँ कि संदर्भ से सत्यता अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) अभिप्रेत है।

(ख) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अभिप्रेत है।

(ग) “प्रसंग” से इन नियमों में उल्लेख प्रसंग अभिप्रेत है;

(घ) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इस अधिनियम में या अनुसंधान और विकास उपकरण अधिनियम, 1986 (1986 का 32) में परिभाषित हैं के वे ही अर्थ होंगे जो क्रमशः उक्त अधिनियमों में दिये गये हैं।

3. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड:—(1) बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(2) बोर्ड के चार सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन की जायेगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त किये गये सदस्य सोम वर्ष की अवधि के लिये परामर्श करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

4. अधिवेशन :—बोर्ड की सामान्यतया वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन ऐसी तारीखों को होंगे जो अध्यक्ष द्वारा कारबार के संव्यवहार के लिये नियत की जायेगी।

5. त्यागपत्र :—(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई सदस्य अपने पद का त्याग बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्तलिखित द्वारा कर सकेगा, जो उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रस्त करेगा।

(2) बोर्ड के सदस्य का पद उस तारीख से रिक्त होगा जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जायेगा।

6. बोर्ड से हटाया जाना :—केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त किये गये किसी सदस्य को हटा सकेगी; यदि :—

- (क) वह विद्वत्-वृत्ति का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा विद्यमान है; या
- (ख) वह एक अन्मोचित दिवालिया है; या
- (ग) वह किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्बलित है; या
- (घ) यदि उसका आचरण सदस्य बने रहने के लायक नहीं पाया गया है।

7. सदस्यों द्वारा हित का प्रकटीकरण :—

बोर्ड के विचार के लिये प्रस्तुत किये गये किसी प्रस्ताव में यदि बोर्ड के किसी सदस्य/या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य का कोई हित है तो सदस्य प्रस्ताव में अपने हित के विस्तार को प्रकट करेगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन की अध्यक्षता करना :—अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में कोई ऐसा अन्य सदस्य जो उपस्थित है बोर्ड द्वारा यथा विनिश्चित है बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन में अध्यक्षता करेगा।

9. गणपूर्ति :—(1) बोर्ड के अधिवेशन में कारबार के संव्यवहार के लिये आवश्यक गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का आधी होगी।

(2) यदि किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष या व्यक्ति जब तक गणपूर्ति न हो तब तक के लिये अधिवेशन स्थगित कर देगा।

(3) जहां उप नियम (2) के अधीन किसी अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया है, ऐसा कारबार जो यदि गणपूर्ति उपस्थित होती तो मूल अधिवेशन में लाया जाता, उसें लाया जायेगा और चाहे गणपूर्ति हो या न हो उसका स्थगित अधिवेशन में संव्यवहार किया जा सकेगा।

10. बोर्ड का अधिवेशन बुलाने की शक्ति :—बोर्ड का अध्यक्ष किसी भी समय बोर्ड का अधिवेशन बुला सकेगा और यदि बोर्ड के कम से कम चार सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन के लिये मांग रखी गई हो तो वह ऐसा कर सकेगा।

11. अधिवेशन और कारबार की सूचना :—स्थगित अधिवेशन को छोड़कर प्रत्येक अधिवेशन में संव्यवहार किये जाने वाले कारबार की सूची, ऐसे अधिवेशन के लिये निश्चित की गई तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य के पते पर बोर्ड के सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भेजी जायेगी और जहां अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति के अन्यथा निवेश के सिवाय किसी अधिवेशन में ऐसे कारबार जिसकी सूचना दी जा चुकी है में भिन्न किसी कारबार को नहीं लाया जायेगा।

12. मतदान :—(1) अधिवेशन में लाए गये सभी मामलों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों और मतदान के बहुमत से किया जायेगा।

(2) अध्यक्ष या किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति समान मत होने की समस्त दशा में दूसरे या निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

13. बोर्ड के अधिवेशन में आमंत्रित व्यक्ति :—बोर्ड का अध्यक्ष, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को बोर्ड के किसी अधिवेशन में भाग लेने के लिये आमंत्रित कर सकेगा किन्तु ऐसे व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

14. कारबार का अभिलेख :—(1) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का अभिलेख अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदन के लिये सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा।

(2) जब किसी कारबार का संव्यवहार कागज पत्रों के परिचालन द्वारा किया जाता है वहां सचिव ऐ संव्यवहार किए गए कारबार का अभिलेख अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के लिए परिचालन का निदेश देने हुए तैयार करेगा।

(3) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन में संव्यवहार किए गए कारबार के अभिलेख का अनुमोदन और हस्ताक्षर अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और कारबार का अनुमोदित लेख बोर्ड के अगले अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) बोर्ड या उसकी समिति द्वारा संव्यवहार किए गए कारबार की मर्तों का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जाएगा।

15. समिति की नियुक्ति :—(1) बोर्ड ऐसी समिति या समितियों का जो बोर्ड आवश्यक समझता है ऐसी शक्तियों के प्रयोग और ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए जो इन नियमों के अधीन प्रत्यापोजित किया जा सके, नियुक्त कर सकेगा।

(2) बोर्ड की सिफारिश पर अध्यक्ष ऐसी समिति या समितियों का जो बोर्ड अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा।

(3) बोर्ड की सिफारिश पर अध्यक्ष, उपनियम (1) के अधीन गठित किसी समिति या समितियों में सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा।

(4) बोर्ड समिति या समितियों के निर्देश निबंधन अवधि, सदस्यता और अन्य संबंधित पहलुओं का अवधारण करेगा।

(5) समिति या समितियां अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट या निष्कर्ष जब तक कि बोर्ड द्वारा विस्तारित नहीं किया गया हो अनुबद्ध समय के भीतर प्रस्तुत करेगी।

16. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य, —अध्यक्ष

(1) बोर्ड या उसकी समितियों के समुचित कार्य करण और बोर्ड या समितियों के विनिश्चय का क्रियान्वयन करना और इन नियमों या अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारी वृन्द पर ऐसा पर्यवेक्षीय और प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा जो अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के दक्षता पूर्ण निर्वाहन के लिए आवश्यक हो सके।

(3) बोर्ड द्वारा किए गए किसी विनिश्चय, ऐसे विनिश्चय या केन्द्रीय सरकार को संबोधित निर्देश के अनुसरण में बोर्ड या इसकी किसी समिति की अपेक्षित कार्यवाही को आस्थागित करना।

(4) ऐसे तात्कालिक मामलों बोर्ड जिनको निपटान की प्रतीक्षा नहीं कर सकता पर विनिश्चय लेना और बोर्ड के अगले अधिवेशन में उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना।

परन्तु यह कि जहां बोर्ड अध्यक्ष द्वारा किए गए विनिश्चय को उपाहित या उलट देता है वहां ऐसे उपांतरण या उलट का ऐसे उपांतरण या उलट से पूर्व की गई किसी कार्यवाही की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17. सचिव की शक्तियां और कर्तव्य, —अध्यक्ष के संपूर्ण पर्यवेक्षण, निदेशन, नियंत्रण और मार्ग दर्शन के अधीन रहते हुए बोर्ड का सचिव —

- (1) बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा;
- (2) बोर्ड के विनिश्चयों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा;
- (3) वित्तीय सहायता और उपकरण के प्रतिदाय के आवेदन पत्र का प्रसंस्करण करेगा;
- (4) बोर्ड के अनुमोदन के लिए बजट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा तैयार कर प्रस्तुत करेगा।
- (5) सूचना जारी करेगा, कार्यसूची/कार्यवृत्त तैयार करेगा और परिचालित करेगा और बोर्ड का अधिवेशन बुलाएगा;

(6) बोर्ड के अनुमोदन से बैंक खाता खोलेगा और बैंक खाते का परिचालन करेगा।

(7) कार्यालय व्यय जिसमें वेतन, आकस्मिकता बजटीय उपबंधों के अधीन रहते हुए स्वीकार करेगा;

(8) बजटीय उपबंधों के अधीन रहते हुए उपस्कर, लेखन सामग्री प्राप्त करने के लिए बोर्ड की ओर से निविदाओं का नियमन और किसी व्यक्ति के साथ संविदा करेगा;

(9) बोर्ड की अनुमति के लिए कर्मचारीवृन्द की संरचना और उनकी सेवा की शर्तें तैयार करेगा तथा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(10) किसी विधि न्यायालय में बोर्ड के हितों की रक्षा के लिए जैसा आवश्यक हो कार्रवाई करेगा; और

(11) अध्यक्ष/बोर्ड द्वारा अपेक्षित समनुदेशित किसी कर्तव्य को करेगा।

18. प्रौद्योगिकी विकास और उसे लागू करने के लिए निधि स्थापित करना— प्रौद्योगिकी विकास और उसे लागू करने के लिए एक निधि गठित की जाएगी जिसमें अनुदान/जमा रकम और विनिधान से आय को अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 10 में विनिर्दिष्ट अन्य धनों के साथ प्रत्यापित किया जाएगा:

परन्तु निधि में जमा की गई किसी रकम को किसी अपीलीय प्राधिकरण या न्यायालय के आदेश द्वारा किसी दावेदार को यथा संदेय किए जाने का आदेश या निदेश होने पर निधि से संदाय किया जाएगा।

19. वित्तीय सहायता के लिए प्रक्रिया —(1) बोर्ड अधिनियम की धारा 6 में यथा उल्लिखित वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगा।

(2) ऐसा कोई आवश्यक जो निधि से वित्तीय सहायता लेने की खांछा रखता है प्ररूप "अ" में बोर्ड को आवेदन करेगा;

(3) बोर्ड का सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र आवेदन का प्रसंस्करण कर सकेगा।

(4) यह बोर्ड या उसके प्राधिकृत अधिकारी के लिए खुला होगा कि —

(क) आवेदक से और कोई सूचना मांगेगा;

(ख) आवेदन से संबंधित किसी पहलू का अन्वेषण करने और उसकी रिपोर्ट करने के लिए किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञों को नियुक्त करना।

(5) जब तक कि आवेदक को मुने जाने का अवसर न दिया गया है, वित्तीय सहायता अनुदान करना नामंजूर नहीं किया जाएगा।

(6) किसी आवेदन पर बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(7) कोई प्राधिकृत अधिकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता का संचितरण बोर्ड द्वारा अधिकृत निबंधन और शर्तों के अनुसार कर सकेगा।

(8) उप-नियम (7) में निर्दिष्ट वित्तीय सहायता का संचितरण बोर्ड द्वारा यथा अभिकथित बोर्ड और आवेदक के मध्य करार के अधीन रहते हुए होगा।

(9) ऋण पर ब्याज का प्रभार बोर्ड द्वारा तथा विनिश्चित दर से किया जाएगा।

(10) ऋण की रकम या उसकी किस्त के प्रतिसंदाय या उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय में किसी धूक की दशा में अतिरिक्त ब्याज जो बोर्ड द्वारा चूक रकम पर विनिश्चित किया जा सकेगा ऋणी द्वारा संदेय होगा।

(11) बोर्ड विशेष परिस्थितियों में ऐसे अतिरिक्त ब्याज के संदाय का भागतः या पूरा अधित्यजन कर सकेगा।

(12) उस पर ब्याज के साथ ऋण का प्रतिसंदाय परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने की एक वर्ष के पश्चात् और किसी भी दशा में ऋण के संचितरण की तारीख से चार वर्ष के अन्त से पूर्व प्रारंभ होगा तथा उस पर शोध ब्याज के साथ पांच वार्षिक किस्तों में वसूलनीय होगा।

(13) करार के उपबंधों के निबंधन में परियोजना के असफल घोषित किए जाने की दशा में, बोर्ड ब्याज और ऋण की वसूली के अधित्यजन पर विचार कर सकेगा; और ऐसी विशेष परिस्थिति में अनुपयोजित अतिशेष रकम बोर्ड को लौटा दी जाएगी तथा सृजित अस्ति बोर्ड द्वारा विनिश्चय की गई रीति से निपटाई जाएगी।

20. बोर्ड और उसकी समितियों के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते :—

(1) सरकारी सेवक से भिन्न बोर्ड या किसी समिति का सदस्य बोर्ड या इसकी विधिवत गठित समिति के अधिवेशन में भाग लेने के प्रयोजन या बोर्ड या उसकी संबंधित समिति द्वारा उसे समनुदेशित किसी कर्तव्य के निर्वहन के प्रयोजन के लिए की गई किसी यात्रा की बाबत तत्समय प्रवृत्त सरकारी उपक्रमों (प्रवर्ग "क") के अधिकारियों को यथा अनुज्ञेय उच्चतम दर पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(2) किसी तदर्थ समिति या किसी अन्य समिति की सेवा करने या बोर्ड के किसी कारबार में भाग लेने के लिए बोर्ड द्वारा विशेष रूप से नाम निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा की गई यात्रा की दशा में उसे अनुज्ञात यात्रा और दैनिक भत्ते बोर्ड द्वारा उस सरकार के नियमों के अधीन तत्समय जिसके अधीन नियोजित है उसे अनुज्ञेय भत्ते की दर से संदेय होगा।

(3) बोर्ड या किसी समिति के सदस्य को यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक कि वह

यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि जिस यात्रा ठहराव की बाबत वाक किया गया है, किसी अन्य स्त्रोत से यात्रा या दैनिक भत्ते नहीं लिए हैं।

(4) बोर्ड या उसकी समिति के किसी सदस्य को यात्रा भत्ता उसके सामान्य निवास से अधिवेशन के स्थान तक या ऐसे स्थान जहाँ वह बोर्ड का कोई कारबार करने के लिए गया है और अपने निवास पर वापस हुआ है तक संदेय होगा।

परन्तु जहाँ यात्रा किसी अन्य स्थान से प्रारंभ होती है और वापसी यात्रा समाप्त होती है वहाँ भत्ता उस रकम तक जो उसे यात्रा सामान्य निवास स्थान से प्रारंभ होकर सामान्य निवास स्थान पर समाप्त होने पर संदेय हुई होती या ऐसी रकम जो उसे की गई वास्तविक यात्रा की वास्तव संदेय होती जो भी कम हो तब तक सीमित होगी।

परन्तु यह और कि किसी विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष सामान्य निवास स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान से किसी सदस्य को यात्रा भत्ता दे सकेगा।

21. वाहन भत्ता :— बोर्ड या किसी समिति के ऐसे सदस्यों को जो यात्रा भत्ता लेता है बोर्ड या बोर्ड के किसी अन्य कारबार समिति के अधिवेशन में भाग लेने के लिए वाहन भत्ता का संदाय नहीं किया जाएगा।

परन्तु बोर्ड या समिति का कोई सदस्य जो उस स्थान जहाँ बोर्ड या किसी समिति का अधिवेशन या जहाँ बोर्ड के किसी अन्य कारबार का संयोजन होता है का निवासी है वहाँ उसे नियम 20 के अधीन अनुज्ञेय दैनिक भत्ते के अतिरिक्त वाहन पर उपगत वास्तविक व्यय का संदाय किया जा सकेगा।

22. यात्रा कार्यालय खोला :— बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य स्थान पर अपना शाखा कार्यालय/कार्यालयों को खोल सकेगा।

23. केन्द्रीय सरकार से परामर्श :— बोर्ड, यदि आवश्यक समझे, समय-समय पर यथा संशोधित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) और अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम, 1986 (1986 का 32) के प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार के सलाह मांग सकेगा।

24. नियमों का निर्वचन :— जहाँ नियमों का निर्वचन संबंधी कोई शंका प्रोद्भूत होती है वह निर्वचन केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

25. शिथिल करने की शक्ति :— जहाँ बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी के प्रचालन से किसी विशिष्ट मामले में कठिनाई पैदा होती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को ऐसे विस्तार तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो मामले को व्यापक तथा साम्यापूर्ण रीति से निपटाने में आवश्यक समझे शिथिल कर सकेगा।

किन्तु ऐसा कोई आदेश केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

26. बोर्ड का प्रधान कार्यालय :- बोर्ड का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा।

27. पुनरीक्षण :- (1) केन्द्रीय सरकार, उसके लिए जो कारण है उसे लेखबद्ध करते हुए, बोर्ड या इसकी समिति के किसी विनिश्चय का पुनर्विचोक्षण कर सकेगा और मामले में जैसा उचित समझे आदेश पारित करेगा।

(2) उस पर केन्द्रीय सरकार के ऐसे आदेश की प्रति यथा स्थिति बोर्ड या संबंधित समिति को केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजी जाएगी।

(3) उपरोक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने पर यथास्थिति बोर्ड या समिति उक्त आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार उक्त अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् उपनियम (1) के अधीन पारित अपने द्वारा पारित आदेश को या तो रद्द, उपान्तरित या पुष्टि कर सकेगी या मामले की बाबत सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार की राय में जो न्याय-संगत या समीचीन हो ऐसी अन्य कार्यवाई करेगी।

प्रारूप—क

[नियम 19(2) देखिए]

महत्वपूर्ण: कृपया इस प्रारूप में बिना किसी तालिक सूचना का दमन करते हुए जो जिसके समागम होने पर इस अधिनियम के अधीन वित्तीय सहायता के लिए इन्कार हो सकेगा पर आधारित स्थापित मामले का मांगा गया सत्य व्योरा दें।

1. आवेदक का नाम और डाक का पूरा पता
2. वित्तीय सहायता मांगने वाले औद्योगिक समुत्पादन, अनु-संधान और विकास संस्था या अन्य अभिकरण का नाम और संस्थापन तारीख:
3. क्या यह सोसायटी अधिनियम 1860 (1860 का 21) या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के रजिस्ट्रीकरण है या किसी अन्य अधिनियम के अधीन सुजित है।
4. यदि हाँ, तो रजिस्ट्रीकरण/सृजन सं. (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की स्थापित प्रति संलग्न करें)
5. क्या संगठन राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर का है
6. प्रबंधक समिति/बोर्ड के पदाधिकारियों के नाम, पते और उपाध्यक्ष और उनकी उपजीविका सहित व्योरे

7. संगठन का संक्षिप्त व्योरा पिछले तीन वर्षों में उसके उद्देश्य और क्रियाकलाप
8. प्रौद्योगिकी की पूर्ण विनिष्टियां (देसी/आयातित)
9. अपेक्षित रकम का प्रयोजन (कृपया परिशोधना का और इसके प्रस्तावित क्रियान्वयन का व्योरा दें)
10. अपेक्षित वित्तीय सहायता की प्रकृति और रकम—आवर्ती/अनावर्ती मदवार व्योरा मन्त्र करे
11. व्यवस्था की गई क्रियाकलाप की समय अनुसूची
12. आवेदक द्वारा उपगत/विनिर्धानित कुल रकम या आवेदक द्वारा संभावित उपगत व्यय:
13. अतिशेष रकम की निधि का स्त्रोत, क्या संगठन किसी अन्य सरकारी/गैर सरकारी स्त्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है, यदि हाँ, तो व्योरा दें।
14. पिछले पांच वर्ष में आवेदक के विरुद्ध सिविल, आपराधिक या कराधान मामलों में किसी विधि न्यायालय में अभियोजन, यदि कोई हो व्योरा दें
15. निम्नलिखित वस्तुओं की प्रतियां संलग्न करें:
 - (i) संगठन का संविधान और यथालागू अनुच्छेद/एसोसिएशन का शापन
 - (ii) वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखा विवरण (पिछले तीन वर्षों का)

घोषणा

(आवेदक या उसके प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा)। इसमें दी गई विनिष्टियां सत्य और सही हैं किसी भी तालिक तथ्य का दमन नहीं किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम स्वीम को शासित करने वाले मार्गदर्शकों/निबंधनों/शर्तों को पढ़ लिया है और अपने संगठन/अपनी संस्था को और से उनके अनुपालन का बंधन होता हूँ/हैं। यदि उपबोधित किया गया तो वित्तीय सहायता का उपयोग यथा घोषित रूप में होगा (जो लागू न हो काट दें)

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरित

[का. सं. II-आईआरडी./1/91 टी. टी.]

एम. एम. के. सरकारना, संपुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 1996

G.S.R. 523(E).—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Technology Development Board Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995).

(b) "Board" means the Technology Development Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "Form" means the form annexed to these rules;

(d) all other words and expressions used in these rules, but defined in the Act or the Research and Development Cess Act, 1986 (32 of 1986) shall have the meaning respectively assigned to them in those Acts.

3. Technology Development Board.—(1) The Board shall be constituted in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Act.

(2) Four members shall be appointed to the Board under clause (g) of sub-section (3) of section 3 of the Act.

(3) The members appointed under sub-rule (2), shall hold office for a period of three years and shall be eligible for re-appointment.

4. Meeting.—The Board shall ordinarily hold at least two meetings in a year on dates to be fixed by the Chairperson for the transaction of business.

5. Resignation.—(1) A member appointed under clause (g) of sub-section (3) of section 3 of the Act, may resign his seat by writing under his hand addressed to the Chairperson of the Board, who shall cause to forward it to the Central Government.

(2) The office of the member of the Board fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the Central Government.

6. Removal from the Board.—The Central Government may remove any member of the Board

appointed under clause (g) of sub-section (3) of section 3 of the Act—

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) if he is an undischarged insolvent; or

(c) if he is convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) if his conduct is found to be undermining of a member.

7. Disclosure of interest by members.—If any member of the Board or his/her family members has any interest in a proposal submitted for consideration of the Board, the member shall disclose the extent of his interest in the proposal.

8. Presiding over the meetings of the Board.—The Chairperson or in his absence, such other member present as is decided by the Board shall preside at every meeting of the Board.

9. Quorum.—(1) The quorum necessary for the transaction of business at a meeting of the Board shall be one-half of the total number of members.

(2) If at any time there is no quorum, the Chairperson or the person presiding over a meeting shall adjourn the meeting until there is a quorum.

(3) Where a meeting has been adjourned under sub-rule (2), the business which would have been brought before the original meeting if there had been a quorum present there at, shall be brought before, and may be transacted at an adjourned meeting whether there is quorum present or not.

10. Power to call Board Meetings.—The Chairperson of the Board may at any time call a meeting of the Board and shall do so if a requisition for that purpose is presented to him by atleast four members of the Board.

11. Notice of meetings and business.—A list of the business to be transacted at every meeting except at an adjourned meeting, signed by the Secretary of the Board or a officer authorised by the Chairperson, shall be sent to the address of each member atleast seven days before the day fixed for such meeting, and no business shall except where the Chairperson or the person presiding over the meeting otherwise directs, be brought before, or transacted at; in any meeting other than the business of which a notice has been so given.

12. Voting.—(1) All matters brought before any meeting of the Board shall be decided by the majority of the votes of the members present and voting.

(2) The Chairperson or the person presiding over a meeting shall have and exercise a second or a casting vote in all cases of equality of votes.

13. Invitees to the Board meetings. The Chairperson of the Board may invite any person or persons to attend any meeting of the Board but such persons shall have no right to vote.

14. Record of business.—(1) The record of business transacted at every meeting of the Board shall be prepared by the Secretary for approval by the Chairperson or the member presiding at such meeting.

(2) When any business is transacted by circulation of papers, the Secretary shall prepare a record of the business so transacted for approval by Chairperson of the Board directing the Circulation.

(3) The record of business transacted at every meeting of the Board shall be approved and signed by the Chairperson or the member presiding at such meeting, and the approved record of business shall be submitted to the Board at its next meeting.

(4) A record shall be maintained by the Secretary of items of business transacted by the Board or the committees thereof.

15. Appointment of Committees.—(1) The Board may appoint such committee or committees as the Board deems necessary to exercise such powers and discharge such functions as may be delegated to it under these rules.

(2) The Chairperson may, on the recommendation of the Board, appoint such Committee or Committees as may be necessary for the efficient discharge of duties of the Board.

(3) The Chairperson, on the recommendation of the Board, coopt members to any Committee or Committees set up under sub-rule (1).

(4) The Board shall determine the terms of reference, tenure, membership and other related aspect of the Committee or the Committees.

(5) The Committee or Committees shall submit its report or finding to the Chairperson of the Board within the stipulated time unless extended by the Board.

16. Powers and duties of the Chairperson.—The Chairperson shall :—

(1) be responsible for the proper functioning of the Board and the committees thereof and the implementation of the decisions arrived at by the Board or by the committee and the discharge of duties imposed on him by these rules of under the provisions of the Act ;

(2) exercise such supervisory and administrative control over all officers and staff of the Board as may be necessary for efficient discharge of functions under the Act.

(3) require the Board or any committee thereof to defer taking action in pursuance of any decision taken by the Board, pending a reference to the Central Government on such decision ;

(4) take decision on urgent matters that cannot wait disposal by the Board and such decisions shall be put up to the Board for approval at its next meeting :—

Provided that where the Board modifies or reverses the decision taken by the Chairperson, such modification or reversion shall be without prejudice to the validity of any action taken before such modification or reversion.

17. Powers and duties of the Secretary.—Subject to the overall supervision, direction, control and guidance of the Chairperson, the Secretary of the Board shall :—

(1) be the Chief Executive Officer of the Board ;

(2) be responsible for implementing the decisions of the Board ;

(3) process applications related to financial assistance and refund of cess ;

(4) cause to prepare and submit the budget proposal, annual report and the annual accounts to the Board for its approval ;

(5) issue notices, prepare and circulate the agenda/minutes and convene meetings of the Board;

(6) open bank accounts with the approval of the Board and regulate the operations of bank accounts ;

(7) sanction office expenses including salaries, contingencies subject to the budgetary provisions;

(8) regulate tenders and entering into contracts with any person on behalf of the Board, for the procurement of equipment, stationery, subject to the budgetary provisions ;

(9) prepare staff structure, and their service conditions, and place before the Board for its approval;

(10) take such actions as may be necessary to defend the interest of the Board at any court of law ; and

(11) carry out any other duties required/assigned by the Chairperson and the Board.

18. Stating up of Fund for Technology Development and Application.—There shall be constituted a Fund for Technology Development and Application into which credits of amounts of grants and income from investment alongwith other monies specified in sub-section (1) of section 9 and section 10 of the Act shall be accredited :—

Provided that any amount having been credited to the Fund is ordered or directed as payable to any claimant by orders of appellate authority or court, shall be paid from the Fund.

19. Procedure for financial assistance.—(1) The Board may provide financial assistance as provided for under section 6 of the Act.

(2) Any applicant who is desirous to seek financial assistance from the Fund, shall apply to the Board in Form A.

(3) The Secretary of the Board or an officer authorised by the Board shall, as soon as may be, after the receipt of an application referred to in sub-rule (2), process the application.

(4) It shall be open to the Board or its authorised officer,

(a) to call for any further information from the applicant;

(b) to appoint expert or experts to make an investigation and report on any aspect relating to the application.

(5) No refusal of grant of financial assistance shall be made unless an opportunity is given to the applicant of being heard.

(6) The decision of the Board on any application shall be final.

(7) An authorised officer may disburse the financial assistance approved by the Board as per the terms and conditions laid down by the Board.

(8) The disbursement of financial assistance referred to in sub-rule (7) shall be subject to an agreement between the Board and the applicant, as laid down by the Board.

(9) The interest to be charged on the loan shall be at a rate as decided by the Board.

(10) In case of any default in repayment of the amount of the loan, or payment of any instalment thereof or interest thereon, an additional interest as may be fixed by the Board on the amount of default shall be payable by the loanee.

(11) The Board may, in part or in full, waive the payment of such additional interest under special circumstances.

(12) The repayment of loan together with interest thereon shall commence one year after the project is successfully completed and in any case before the end of the fourth year from the date of disbursement of loan, and the loan amount along with interest due thereon shall be recoverable in five annual instalments.

(13) In case of the project having been declared as a failure in terms of provisions of the agreement, the Board may consider waiving of the recovery of the interest and the loan amount; and in such an eventuality, the unutilised balance amount shall be refunded to the Board and the assets created shall be disposed of in a manner decided by the Board.

20. Travelling and other Allowance to Members of the Board and its Committees.—(1) A member

of the Board or any Committee other than a Government servant, shall be entitled to draw, in respect of any journey performed by him for the purpose of attending a meeting of the Board or of a duly constituted Committee thereof or for the purpose of discharging any duty assigned to him by the Board or the Committee concerned, travelling allowances and daily allowances at the highest rates as admissible to the officials of the Government Undertakings' (Category 'A') for the time being in force.

(2) In case of any journey performed by an official of the Central or the State Government especially nominated by the Board to serve on any adhoc Committee or any other Committee or to attend to any other business of the Board, the Travelling and Daily Allowances admissible to him shall be payable by the Board, at rates admissible to him under the rules of the Government under which he is for the time being employed.

(3) No Travelling Allowance or Daily Allowance shall be allowed to a member of the Board or of any Committee unless he certifies that he has not drawn any Travelling or Daily Allowance from any other source in respect of the journey and halt for which the claim is made.

(4) Travelling Allowance shall be payable from the usual place of residence of member of the Board or any of the Committees to the place of the meeting or the place where he has gone to attend to any business of the Board and back to his place of residence.

Provided that when the journey commences from or the returned journey terminates at any other place the Travelling Allowances shall be limited to the amount that would have been payable had the journey commenced from or terminated at the usual place of residence, or to the amount payable in respect of the actual journey undertaken whichever is less:

Provided further that in special circumstances the Chairperson may grant Travelling Allowance from places other than the usual place of residence of a member.

21. Conveyance Allowances.—No Conveyance Allowance for attending meetings of the Board or any of the Committees of any other business of the Board shall be paid to those members of the Board or any of the Committees who draw Travelling Allowance:

Provided that a member of the Board or the Committees who is resident at a place where the meeting of the Board or any of the Committees is held or where any other business of the Board is transacted, may be paid the actual expenditure incurred on conveyance by him in addition to the daily allowance, as admissible under rule 20.

22. Opening of Branch Offices.—The Board may with the prior approval of the Central Government, set up its branch office/offices at any other place.

23. Consultation with the Central Government.—The Board may, if consider necessary, seek the advice of the Central Government for the administration of the Technology Development Board Act, 1995

(44 of 1995), and the Research and Development Cess Act, 1986 (32 of 1986), as amended from time to time.

24. Interpretation of rules.—Where any doubt arises as to the interpretation of these rules, interpretation shall be referred to the Central Government for its decision.

25. Power to relax.—Where the Board is satisfied that the operation of any of these rules, causes undue hardship in any particular case, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided that no such order shall be made, except with the previous approval of the Central Government.

26. Head office of the Board.—The Head Office of the Board shall be at Delhi.

27. Revision.—(1) The Central Government may, for reasons to be recorded in writing, review any decision of the Board, or its Committees and pass such order in the matter as it think fit.

(2) A copy of such order of the Central Government shall thereupon be sent to the Board or the Committee concerned, as the case may be, by the Central Government.

(3) On receipt of a copy of the order as aforesaid, the Board or the Committee, as the case may be, may make a representation to the Central Government against the said order and the Central Government may after considering the said representation, either cancel, modify or confirm the order passed by it under sub-rule (1) or take such other action in respect of the matter as may in the opinion of the Central Government, be just or expedient having regard to all the circumstances of the case.

FORM-A

[See rule 19 (2)]

Important : Please fill up this form furnishing correct details sought for based on verifiable true state of affairs without causing suppression of any material information which if resorted to shall entail refusal of the financial assistance under the Act :

1. Name and full postal address of the applicant.
2. Name of the industrial concern, research and development institution or other agency seeking/ applying for financial assistance and its date of establishment.
3. Whether registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any other relevant

Act or created under any other Act.

4. If yes; number and year of registration/creation (Attested copy of registration certificate to be enclosed).
5. Whether the organisation is of national/state level.
6. Details of the Managing Committee/Board alongwith names, addresses and occupation of the office bearers.
7. Brief details of the organisations, objectives and activities during the last three years.
8. Complete particulars of technology (indigenous/imported).
9. Purpose for which the amount is required (Please state the details of the project and its proposed implementation).
10. Amount and nature of financial assistance required, item-wise details under recurring/non-recurring to be enclosed.
11. Time schedule of the activities arranged.
12. The total amount incurred/ invested by the applicant, or likely to be incurred by the applicant.
13. Sources of funding of balance amount whether the organisation is getting financial assistance from any other official/non-official source. If yes, give details.
14. Details of prosecution, if any, in a court of law launched against the applicant, during the last five years in civil, criminal or taxation matters.
15. Copies of the following documents to be attached :
 - (i) Constitution of the organisation and Articles/Memorandum of Association as applicable.
 - (ii) Annual Reports and audited statements of accounts (last three years).

DECLARATION

(to be signed by the applicant or its authorised agent)

The particulars heretofore given are true and correct. Nothing material has been suppressed. It

is certified that I/we have read the guidelines, terms and conditions governing the scheme and undertake to abide by them on behalf of our organisation/institution. The financial assistance, if provided, shall be put to the declared use. (Strike out whichever is inapplicable).

APPLICANT/AUTHORISED SIGNATORY

[File No. II-JRD/1/94-TT]

M. M. K. SARDANA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1996

सा. का. नि. 524 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 (1986 का 32) की धारा 10 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसंधान और विकास उपकर नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएँ :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :—

(क) "अधिनियम" से अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 (1986 का 32) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकृत व्योहारी" से विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 6 के अधीन विदेशी मुद्रा का व्यवहार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) "बोर्ड" से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अभिप्रेत है

(घ) "प्रारूप" से इन नियमों से उपावद्ध प्रारूप अभिप्रेत है ;

(ङ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं किन्तु प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का

44) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियमों में हैं।

3. उपकर का उपयोग :—अधिनियम की धारा 3 के अधीन उपकर के उपयोग के प्रयोजन के लिए संदाय :—

(क) किसी विदेशी सहयोग करार के निबंधन में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित या समय-समय पर यथा प्रवृत्त भारत सरकार की औद्योगिकी नीति के अनुसार अनुमोदित प्रौद्योगिकी के आयात के लिए किया गया संदाय ;

(ख) किसी विदेशी सहयोग करार के निबंधन में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित या समय-समय पर यथा प्रवृत्त भारत सरकार की औद्योगिकी नीति के अनुसार अनुमोदित रेखाचित्र और स्पांकिन लागत के लिए किया गया संदाय ;

(ग) किसी विदेशी सहयोग करार के निबंधन में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार या समय-समय पर यथा प्रवृत्त भारत सरकार की औद्योगिकी नीति के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किसी विदेशी सहयोगकर्ता या अन्य व्यक्ति को या भारत में तकनीकी कामकाज की प्रतिनियुक्ति के संबंध में किया गया संदाय ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य तकनीकी के आयात के लिए किया गया संदाय।

4. उपकर संदाय की रीति :—(1) किसी औद्योगिक संस्थान द्वारा अधिनियम की धारा 3 के अधीन संवेद्य उपकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (3) में विनिर्दिष्ट अभिकरण के किसी कार्यालय को केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति एवं संदाय) नियम, 1983 के अधीन विहित जालान प्रारूप के साथ संवत्त किया जाएगा ;

(2) प्रौद्योगिकी आयात के लिए कोई संदाय करते समय या उनसे पूर्व प्रत्येक औद्योगिक समुत्थान ऐसे प्राधिकृत व्योहारी को जिसके माध्यम से ऐसा संदाय किया गया है इस अधिनियम के अधीन संवेद्य उपकर के संदाय के साक्ष्यस्वरूप उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रारूप का प्रतियोग प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां उक्त संदाय प्रतिमर्ष के साथ नहीं किया जाता है वहां प्राधिकृत व्योहारी ऐसे संदाय को लेने से इंकार नहीं करेगा किन्तु तीस दिन की अवधि के भीतर तथ्यों की रिपोर्ट को करेगा।

5. सांख्यिकीय और अन्य सूचना प्रस्तुत करना :—

(1) प्रत्येक औद्योगिक समुत्थान इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से सात दिन के भीतर अधिनियम की धारा 8

में विनिर्दिष्ट सूचना प्रारूप क" में किसी अस्थिरवस्तु विशेषी सहयोग प्रमाणपत्र के अधीन भ्रमणित या आयात की जाने वाली प्रौद्योगिकी की अन्तर्वस्तु विनिर्दिष्टियों के साथ बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ;

(2) जहाँ कोई औद्योगिक समुत्थान इस नियमों के आरंभ के पश्चात् प्रौद्योगिकी के आयात के लिए कोई विदेशी सहयोग करार करता है वहाँ वह अधिनियम की धारा 8 में विनिर्दिष्ट सूचना ऐसा करार करने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रारूप क" में बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ;

(3) उपरोक्त उपनियम (1) और (2) के अधीन प्रस्तुत की गई विनिर्दिष्टियों में किसी परिवर्तन या उपान्तरण को संबंधित समुत्थान द्वारा बोर्ड को सूचित किन्तु किसी भी वक्ता में ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन के प्रवृत्त होने की तारीख से तीस दिन के पश्चात् नहीं बोर्ड को सूचित करेगा ;

6. बकाया उपकर की वसूली की रीति :—(1) नियम 5 के अधीन किसी औद्योगिक समुत्थान द्वारा प्रस्तुत की गई सांख्यिकीय और अन्य सूचना की संवीक्षा करने पर या निम्न 4 के अधीन किसी प्राधिकृत व्यक्तिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड यदि यह पाता है कि किसी औद्योगिक समुत्थान ने उपकर का संदाय नहीं किया है या अधिनियम की धारा 3 के अधीन संदेय रकम से कम रकम का संदाय किया है तो वह ऐसे औद्योगिक समुत्थान को यथास्थिति उपकर या शोध उपकर के अन्तर का संदाय ऐसी सूचना प्राप्त करने की तारीख के तीस दिन के या ऐसे विस्तारित समय के जो बोर्ड लेखबद्ध रूप में अनुज्ञा दे, के भीतर विनिर्दिष्ट अधिकारण को संदाय करने की नोटिस जारी करेगा ;

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट समय सीमा समाप्त हो जाते पर कोई औद्योगिक समुत्थान नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने में असफल हो जाता है और बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि रकम केन्द्रीय सरकार को शोध है, वहाँ इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे औद्योगिक समुत्थान से रकम की वसूली करने की कार्यवाही केन्द्रीय सरकार को शोध राशि के रूप में इस प्रकार करेगा माने ऐसी बकाया रकम भू-राजस्व हो ।

(3) केन्द्रीय सरकार को शोध राशि की वसूली के प्रयोजन के लिये इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी शोध रकम विनिर्दिष्ट करते हुए अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और उसे उस जिले के कलेक्टर को भेजेगा जिसमें औद्योगिक समुत्थान का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या कारबार का प्रधान स्थान है और उक्त कलेक्टर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर उसमें विनिर्दिष्ट रकम की औद्योगिक समुत्थान से वसूली की उत्तरदायी कार्यवाही करेगा सभी बकाया रकम भू-राजस्व हो ।

7. जांच करने की रीति :—(1) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व औद्योगिक समुत्थान के कार्यों की जांच करने के लिये बोर्ड अपने एक या अधिक अधिकारियों को लिखित रूप से प्राधिकृत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी औद्योगिक समुत्थान को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या कारबार के प्रधान स्थान को संबोधित यह निवेश देते हुए नोटिस जारी करेगा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट शास्ति उस पर क्यों नहीं अधिरोपित की जाये ।

(3) उक्त नोटिस की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर औद्योगिक समुत्थान संबंधित अधिकारी को ऐसे वस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों जिस पर उत्तर का विश्वास किया जाए की प्रति के साथ जवाब भेजेगा ।

(4) उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी यदि औद्योगिक समुत्थान द्वारा ऐसा निवेदन किया जाता है तो औद्योगिक समुत्थान की बकाया उपकर के संबंध में अपने निर्णय को स्पष्ट करने में समर्थ करने के लिये वैयक्तिक रूप से सुन सकेगा ।

(5) यदि जांच के किसी प्रक्रम पर उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि व्यक्तिक्रम अच्छे और पर्वत कतरणों से भ्रमा है तो वह अपने की जांच कार्यवाही नहीं करेगा और इस तथ्य की रिपोर्ट बोर्ड को देगा ।

(6) यदि उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी का जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि औद्योगिक समुत्थान द्वारा किया गया व्यक्तिक्रम बिना अच्छे और व्याप्त कारणों के किया गया है तो वह इसकी रिपोर्ट बोर्ड को भेजेगा ;

(7) उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने पर बोर्ड औद्योगिक समुत्थान पर ऐसी शास्ति जैसी वह उचित समझे जो बकाया रकम से वसूली से अनधिक हो अधिरोपित करेगा ;

(8) उपनियम (7) के अधीन अधिरोपित शास्ति की वसूली नियम 6 के उपनियम (3) में प्राधिकृत प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी ।

8. उपकर प्रतिदाय की रीति :—(1) कोई ऐसा औद्योगिक समुत्थान जो वृत्तिपूर्ण संगणना या उपकर के प्रयोजन के लिये संदेय रकम के पुनरीक्षण के कारण अधिक संदाय के प्रतिदाय की माँछ करता है, समर्थकानी दस्तावेजों के साथ बोर्ड के सचिव को लिखित रूप में आवेदन करेगा ;

(2) बोर्ड द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन की संवीक्षा करने के पश्चात् प्राप्त शोध रकम का प्रतिसंदाय करेगा ।

(3) प्रतिदाय के लिये आवेदन पर त्रिनिश्चय आवेदन प्राप्त होने के छह मास के भीतर संसूचित किया जाएगा और प्रतिदाय, यदि कोई है तो उसके साठ दिन के पश्चात् किया जाएगा ।

(4) ऐसे प्रतिदाय पर बोर्ड द्वारा कोई व्याज, प्रसंस्करण या अन्य प्रकार संदेय नहीं होगा ।

9. नियमों का निर्वचन—जहाँ इन नियमों के निर्वचन संबंधी कोई शंका होती है तो यह केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के लिये विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

10. निरसन और व्यावृत्ति—अनुसंधान और विकास उपकरण नियम, 1987 का निरसन किया जाता है :

परन्तु ऐसे निरसन का निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा—

- (क) उक्त नियमों का पूर्व प्रवर्तन या उनके अधीन सम्पन्न रूप से की गई या न की गई कोई बात,
- (ख) उक्त नियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या
- (ग) उक्त नियमों के अधीन उपकरण के असंदाय की बाबत उपगत कोई शास्ति; या
- (घ) यथा उपरोक्त, ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व या शास्ति की बाबत कोई अन्वेषण या उपचार और ऐसा कोई अन्वेषण या उपचार उसी प्रकार संस्थित, किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा तथा ऐसी कोई शास्ति उसी प्रकार अधिरोपित की जा सकेगी जो मानो उक्त नियमों का निरसन नहीं किया गया है।

प्ररूप क

[नियम 5(1) और (2) देखिए]

घोषणा

प्रायोजित प्रौद्योगिक की विशिष्टियाँ

1. प्रौद्योगिक आयात करने वाले प्रौद्योगिक समुत्पान का नाम और पता
2. भारत से बाहर के पक्षकार का नाम और पता जो प्रौद्योगिकी प्रदान कर रहा है (सहयोग)
3. विदेशी सहयोग के लिए भारत सरकार की अनुमति की संख्या और तारीख —
4. विदेशी सहयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की सं. और तारीख
5. विदेशी सहयोग करार की तारीख —
6. विदेशी सहयोग करार की प्रकृति का वर्णन करें
(क) तकनीकी या वित्तीय या तकनीकी और वित्तीय—
(ख) डिजाइन / रेखांकन
7. विदेशी तकनीकी कार्मिकों के संलग्न करने की अवधि, यदि कोई हो, विवरण दें।
8. विदेशी तकनीकी कार्मिकों को संलग्न करने के भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की संख्या और तारीख।
9. वह अवधि जिसके दौरान तकनीकी का अन्तरण होने की संभावना है।
10. विदेशी तकनीकी कार्मिकों को संलग्न करने के लिए विदेशी सहयोग करार के अधीन प्रौद्योगिक

आयात की संदेय रकम और सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संदाय।

(संदाय की अवधि, करोंसी और रकम, जिसमें प्रौद्योगिकी आयात के संबंध में रुपए में किया गया स्थानीय संदाय भी है, का वर्णन करें)

11. ऊपर सब 10 के अधीन संदेय रकम की बाबत संदाय की रीति
12. सहयोगकर्ता को पहले भेजी गई रकम (तारीख सहित) (इस प्ररूप को भरने की तारीख तक)
13. वह अवधि (यदि कोई हो), जिसके लिए रकम भेजी गई है।
14. प्राधिकृत व्यौहारी, यदि कोई हो, का नाम और पता जिसके माध्यम से रकम भेजी गई है या भेजी जाती है।

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

स्थान :

(प्रौद्योगिक समुत्पान की ओर से)

[फा. सं. II-आई.आर.जी./1/94-टी.टी.]

एम. एम. के. सरदाना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 1996

G.S.R. 524(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Research and Development Cess Act, 1986 (32 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Research and Development Cess Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Research and Development Cess Act, 1986 (32 of 1986);
- (b) "Authorised dealer" means any person authorised by the Reserve Bank of India to deal in foreign exchange under section 6 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973);
- (c) "Board" means the Technology Development Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995);
- (d) "Form" means the form annexed to these rules;

- (e) all other words and expressions used in these rules, but defined in the Act or the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995), shall have the meaning respectively assigned to them in those Acts.

3. Levy of Cess.—For the purpose of levy of cess under section 3 of the Act, 'payment' shall include:—

- (a) payment made towards import of technology as approved by the Central Government in terms of any foreign collaboration agreement, or approved in accordance with the Industrial Policy of the Government of India, in force, from time to time.
- (b) payment made towards the cost of drawings and designs in terms of any foreign collaboration agreement as approved by the Central Government or approved in accordance with the Industrial Policy of the Government of India, in force from time to time;
- (c) payment made to foreign collaborators or to any other person for or in connection with deputation of technical personnel to India in terms of any foreign collaboration agreement, in accordance with the approval granted by the Central Government or approved in accordance with the Industrial Policy of the Government of India, in force, from time to time;
- (d) any other payment made towards the import of technology approved by the Central Government.

4. Manner of payment of cess.—(1) The cess payable under section 3 of the Act by an industrial concern shall be paid to any office of a specified agency referred to in clause (g) of section 2 of the Act, along with the form of challan prescribed under the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983.

(2) Every industrial concern shall, on or before making any payment towards the import of technology, furnish to the authorised dealer through whom such payment is made the counter-foil of the form referred to in sub-rule (1) evidencing the payment of cess payable under the Act :

Provided that where such payment is not accompanied by the said counter foil, the authorised dealer shall not refuse to accept such payment but report the fact within a period of thirty days to the Board.

5. Furnishing of statistical and other information.—(1) Every industrial concern shall, within sixty days from the date of commencement of these rules, furnish the information referred to in section 8 of the Act to the Board in Form A containing the particulars of the technology imported or to be imported under any subsisting foreign collaboration agreement.

(2) Where any industrial concern enters into a foreign collaboration agreement for the import of technology after the commencement of these rules, it shall furnish the information referred to in section 8 of the Act to the Board in Form A within thirty days from the date of entering into the agreement.

(3) Any change or modification in the particulars furnished under sub-rule (1) and (2) above, shall be communicated by the industrial concern to the Board immediately but in no case later than thirty days from the date of effecting the modification or change.

6. Manner of recovery of arrears of cess.—

(1) If on a scrutiny of the statistical and other information furnished by an industrial concern under rule 5 or on the basis of a report furnished by any authorised dealer under rule 4 or otherwise, it appears to the Board that an industrial concern has not paid the cess or paid an amount lesser than what is payable under section 3 of the Act, it shall issue a notice to such industrial concern calling upon it to pay the cess or, as the case may be the difference of cess due, to a specified agency within thirty days of the date of receipt of such notice or within such extended time as the Board may permit in writing.

(2) Where on the expiry of the time-limit specified in the notice under sub-rule (1), any industrial concern fails to pay the amount specified in the notice and the Board is satisfied that the amount of cess is due to the Central Government, the officer authorised by the Board in this behalf shall proceed to recover the amount from such industrial concern as sums due to the Central Government as if it were an arrears of land revenue.

(3) For the purpose of recovery of sums due to Central Government, an officer of the Board authorised in this behalf by the Board, may prepare a certificate signed by him specifying the amount due and send it to the Collector of the district in which the industrial concern has its registered office or principal place of business and the said Collector on receipt of such certificate, shall proceed to recover from the said industrial concern the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue.

7. Manner of holding inquiry.—(1) Before imposing any penalty under sub-section (2) of section (9) of the Act the Board shall authorise in writing one or more of its officers to make inquiry into the affairs of the industrial concern.

(2) The officer authorised under sub-rule (1) shall issue to the industrial concern a notice addressed to the registered office or principal place of business directing it to show cause as to why the penalty specified in the notice should not be imposed.

(3) The industrial concern may, within thirty days from the date of receipt of the said notice, send to the officer concerned a reply together with copies of documentary or other evidence relied on in such reply.

(4) The officer authorised under sub-rule (1) may, if so requested by the industrial concern, give a personal hearing to enable the industrial concern to explain its stand in regard to the arrears of cess.

(5) If at any stage of inquiry, the officer authorised under sub-rule (1) is satisfied that the default was on account of good or sufficient reason he shall not proceed further with the inquiry and report the fact to the Board.

(6) If the officer authorised under sub-rule (1) is satisfied after inquiry that there was no good or sufficient reason for the default committed by the industrial concern, he shall send his report to the Board.

(7) On receipt of the report of the officer authorised under sub-rule (1), the Board shall impose on the industrial concern, such penalty as it deems fit not exceeding ten times the amount of arrears.

(8) The penalty imposed under sub-rule (7) shall be recoverable in accordance with the procedure laid down in sub-rule (3) of rule 6.

8. Manner of refund of Cess.—(1) An industrial concern desiring refund of cess paid in excess on account of wrong calculation or revision of payable amounts for the purposes of cess shall apply to the Secretary of the Board in writing with all the supporting documents.

(2) After scrutiny of the application in accordance with the procedure laid down by the Board the dues as found eligible shall be refunded.

(3) The decision on the application for refund shall be communicated within six months of the receipt of the application and the refund, if any, shall be made within sixty days thereafter.

(4) No interest, processing or any other charges shall be payable on such refund by the Board.

9. Interpretation of the rules.—Where any doubt arises as to the interpretation of these rules,

it shall be referred to the Central Government for its decision.

10. Repeal and saving.—The Research and Development Cess Rules, 1987 are hereby repealed :

Provided that such repeal shall not effect—

- (a) the previous operation of the said rules or anything duly done or suffered thereunder ; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said rules ; or
- (c) any penalty incurred in respect of non-payment of cess under the said rules ; or
- (d) any investigation or remedy in respect of such right, privilege, obligation, liability or penalty as aforesaid, and any such investigation or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty may be imposed as if the said rules had not been repealed.

FORM A:

[See rule 5(1) and (2)]

(DECLARATION)

Particulars of technology imported :

1. Name and address of the industrial concern importing technology.
2. Name and address of the party outside India providing technology (collaborator).
3. Number and date of Government of India's approval for the foreign collaboration.
4. Number and date of Reserve Bank of India's approval for the foreign collaboration.
5. Date of foreign collaboration agreement.
6. State the nature of the foreign collaboration, agreement whether—
 - (a) technical or financial, or technical and financial;
 - (b) design/drawings.
7. State the period for engagement of foreign technical personnel, if any.
8. Number and date of Reserve Bank of India approval for engagement of foreign technical personnel.

- | | |
|---|--|
| 9. Period during which technology is likely to be transferred. | 12. Amount already remitted (including dates) to collaborator (as on date of filling this form). |
| 10. Amount payable towards the import of technology under foreign collaboration agreement, for engagement of foreign technical personnel and any other payment approved by the Government. (State the period, currency and amounts to be paid including local payments made in rupees in connection with import of technology). | 13. Period (if any) for which the amount has been remitted. |
| 11. Mode of payment in respect of amounts payable under item 10 above. | 14. Name and address of the authorised dealer, if any, through whom the amount is remitted or is to be remitted. |
- Date :
Place :
- Authorised signatory
(on behalf of the industrial concern)
[File No. II-IRD/1/94-TT]
M. M. K. SARDANA, Jt. Secy.

